भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-961
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

आंध्र प्रदेश के लिए पीएम उषा के अंतर्गत धनराशि जारी करना

†961. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पीएम उषा के अंतर्गत धनराशि जारी करने में देरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) आंध्र प्रदेश के लिए धनराशि जारी करने में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या आंध्र प्रदेश के लिए पीएम उषा समर्थित इकायों की संख्या बढाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार की स्टार्स परियोजना के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

पीएम-उषा हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड की पहली और दूसरी बैठक में, इस योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 275 करोड़ रुपये की राशि के साथ आंध्र प्रदेश में 25 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। पिछले पांच वर्षों (अर्थात 2019-20 से 2023-24) में राज्य को 88.72 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान, रूसा/पीएम-उषा योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा कुछ शर्तों जैसे कि उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना, संबंधित राज्य के हिस्से का हस्तांतरण, पहले से जारी धनराशि का कम से कम 75% उपयोग, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा निर्धारित शर्तों का राज्यों द्वारा अनुपालन, वित्त मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन और वित्तीय वर्ष में धन की उपलब्धता, को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। वर्तमान में राज्य के एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) बैंक खाते में 42.75 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

(घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में, स्टार्स परियोजना को छह राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा वर्तमान में इन छह राज्यों के अलावा किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजना का दायरा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

*****